खेल में नए खिलाड़ी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

07 जनवरी, 2022

जापान-ऑस्ट्रेलिया रक्षा समझौता संकेत देता है कि मध्य शक्तियाँ इंडो-पैसिफिक में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार हैं।

रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट , ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच रक्षा संधि, एशिया और इंडो-पैसिफिक के लिए इसके रणनीतिक महत्व के अलावा, उन रुझानों को मजबूत करता है जो इस क्षेत्र में बदलते सुरक्षा ढांचे का हिस्सा हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो यह द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय समूहों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में यूएस-केंद्रित दृष्टिकोण से दूर जाने का प्रतीक है। यह इस बात का भी संकेत है कि जापान इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है।

एशिया और इंडो-पैसिफिक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था उभरी, वह विभिन्न सुरक्षा भागीदारों के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों द्वारा चिह्नित की गई थी। यह यूरोप में अमेरिकी रणनीति के विपरीत था, जहाँ नाटो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजिंग के उदय के साथ, ऐसा लगता है कि यह बदल रहा है।

चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (या क्वाड, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ) उसके बाद AUKUS, और अब जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट - अमेरिका के दो संधि सहयोगी - सभी एक से अधिक सशक्त और प्रतिबद्ध क्षेत्रीय रणनीतिक नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं।

जापान अन्य कारकों के साथ-साथ, उनके गहरे आर्थिक संबंधों के बावजूद, स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के सवाल पर चीन के सामने खड़े होने की ऑस्ट्रेलिया की इच्छा से सक्षम हुआ है। जापान के लिए, यह अपने दृष्टिकोण और वैश्विक छवि में हालिया विकास के साथ एक टुकड़े की एक और भी बड़े बदलाव का प्रतीक है। अब तक, जापान का एकमात्र प्रमुख रक्षा सहयोगी अमेरिका ही था।

सामरिक क्षेत्र में नेतृत्व करने में यह मितव्ययिता द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत से प्रेरित थी, और यह तथ्य कि जापान एक शाही शक्ति था, जिसने इस क्षेत्र के कई देशों को इससे सावधान कर दिया था। फिर भी, हाल ही में, वियतनाम और फिलीपींस दोनों ने बीजिंग के खिलाफ एक गढ़ प्रदान करने के लिए टोक्यो की ओर देखा है, जो एक रणनीतिक साझेदार के रूप में जापान की भूमिका की अधिक स्वीकृति का संकेत देता है। और टोक्यो अब अपने संबंधों का और विस्तार भी कर रहा है: रिपोर्टों से पता चलता है कि यह यूके और फ्रांस के साथ भी रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट जैसे समझौतों की तलाश करेगा।

रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट के प्रति चीन की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है, जो पहले न्यूट्रल था अब नकारात्मक हो चुका है। यह संधि मध्य शक्तियों को अपने सहयोग का विस्तार करने और क्वाड द्वारा बनाई गई गति पर निर्माण करने के लिए अपने आक्रामक रुख पर जोर देती है। नई दिल्ली ने अपने हिस्से के लिए, सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए बहुत कुछ किया है – इसमें टोक्यो और कैनबरा दोनों के साथ "2+2" मंत्रिस्तरीय संवाद हैं। इस जुड़ाव को और बढ़ाना होगा, साथ ही इस क्षेत्र के अन्य भागीदारों तक पहुँचना होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में किन दो देशों ने इंडो-पैसेफिक क्षेत्र में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किया है?

(क) ब्रिटेन-फ्रांस

(ख) अमेरिका-जापान

(ग) जापान-ऑस्ट्रेलिया

(घ) जापान-भारत

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Which two countries have recently signed Reciprocal Access Agreement in the Indo-Pacific region?

(a) Britain-France

(b) America-Japan

(c) Japan-Australia

(d) Japan-India

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. इंडो-पैसेफिक क्षेत्र में चीन को प्रतिसन्तुलित करने में अब रणनीति अमेरिका केंद्रित न होकर जापान केंद्रित बनती जा रही है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? टिप्पणी करें। (250 शब्द)

Q. The strategy to counter China in the Indo-Pacific region is now shifting from US-centric to Japan-centric. Do you agree with this statement? Comment. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।